दी जाती है । दालों का आयात करने के ठेकों के लिए नेफेड पंजीकरण करने वाला प्राधिकरण है और इसने 1990-91 के दौरान (जून, 1990 तक) 132.27 करोड़ रुपये मूल्य की 2.09 लाख मीटरी टन दालों का आयात करने के लिए ठेकों का पंजीकरण किया है । सरकारी खाते पर दालों का आयात करने का इस समय कोई विचार नहीं है । तथापि, सरकार दालों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

(ग) दालों पर आयात शुल्क 35 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 1-11-1989 से 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया था । दालों पर लगाए गए आयात शुल्क में और कमी करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

3711. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग चार दशकों से सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चल रही है,

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 1989 के अन्त तक कितने प्रतिशत परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है तथा सरकार ने कुल कितने प्रतिशत परिवारों को इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो ऐसी योजना तैयार न कर पाने के क्या कारण हैं ?

श्रम एवम् कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है । परिवार आधार पर आरक्षण देने की कोई योजना नहीं है । विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न अर्हताएं अपेक्षित होती हैं और भर्तियां केवल शैक्षिक आदि अर्हताओं और उपयुक्तता के आधार पर ही की जाती है ।

3712. [Transferred to the 4th September 1990.]

वनस्पति घी का उत्पादन

3713. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वनस्पति घी के उत्पादन में लगातार गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष इन्हीं महीनों के दौरान वनस्पति घी का औसत उत्पादन कितना-कितना हुआ था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादन में कमी होने तथा कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण वनस्पति घी के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो जुलाई, 1990 में खुले बाजार में वनस्पति घी का मूल्य कितना था तथा आगामी त्यौहार के महीनों में मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वनस्पति के उत्पादन में कुछ गिरावट आई है ।

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 82000 मी. टन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वनस्पति का औसत मासिक उत्पादन 76200 मी. टन है ।

(ग) कच्चे माल की उपलब्धता में रुकावट और उसके ऊंचे मूल्यों के कारण वनस्पति के मूल्य ऊंचे हुए हैं ।

(घ) देश के विभिन्न केन्द्रों में खुले बाजार में वनस्पति के 15 कि. ग्राम के एक टिन का औसत खुदरा मूल्य लगभग 500/- रुपये से 550/- रुपये था। आगामी त्यौहार के मौसम के दौरान वनस्पति के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) हाल के महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आयातित तेल की आपूर्ति बढ़ा दी गई है ।

(2) थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं तथा खाद्य तेल और वनस्पति के विनिर्माताओं के पास स्टाक सीमा में कमी की गई है ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशानुसार बैंक अग्रिमों के लिए न्यूनतम अन्तर में वृद्धि ।

(4) जमाखोरी विरोधी अभियान चलाने और आवश्यक वस्तुओं की मूल्य रेखा समान रखने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।

(5) वनस्पति के विनिर्माण में लघु और अपराम्परागत तेलों के प्रयोग पर उत्पाद शुल्क में छूट की अनुमति दी गई है ।

चीनी की उत्पादन लागत का विश्लेषण

3714. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अगस्त, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "सुगर लाइकली टू फ्लेयर अप डेस्पाइट रिलीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और यदि हां, तो क्या यह सच है कि चीनी उत्पादक उत्पादन लागत के बढ़ जाने के कारण चीनी के मूल्यों में कमी करने के लिए तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी की उत्पादन लागत का ब्यौरेवार विश्लेषण किया है; और

(ग) क्या गन्ना, इंधन, मशीनरी, श्रम, प्रबन्ध, सरकारी करों तथा खर्च की अन्य मदों पर आयी लागत को उत्पादन लागत में शामिल किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है । सरकार खुले बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी की उचित कीमत पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करती रहेगी ।

(ख) और (ग) चीनी फैक्ट्रियों से चीनी उत्पादन का 45 प्रतिशत हिस्सा देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को समान खुदरा कीमतों पर वितरण के लिए ले लिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त चीनी की क्षेत्रीय एक्स-फैक्ट्री कीमतें, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गन्ने की न्यूनतम कीमत और औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निकाली गई परिवर्तन लागत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। परिवर्तन लागतों को सिफारिश करते समय बी. आई. सी. पी. मजदूरी, उर्जा, इंधन, खर्च की अन्य मदों आदि के रूप में परिवर्तन लागत से संबद्ध खर्च को ध्यान में रखती है । लेवी चीनी की क्षेत्रीय एक्स-फैक्ट्री कीमतों के परिकलन के लिए राज्य सरकारों द्वारा गन्ने पर लगाए गए करों को भी ध्यान में रखा जाता है ।